

60% मतदाताओं ने आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा

प्रलिस के लिये:

नरिवाचन आयोग (EC), आधार संख्या, पुट्टासुवामी मामला (नजिता का अधिकार), डजिटल वयक्तगित डेटा संरक्षण वधियक, 2022

मेन्स के लिये:

भारत में आधार लकिगि की स्थिति, आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने से संबंधित मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

[नरिवाचन आयोग](#) के अनुसार, भारत के 94.5 करोड़ मतदाताओं में से 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने [आधार नंबर](#) को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा है।

भारत में आधार लकिगि स्थिति:

- त्रपुरा में आधार लकिगि दर उच्चतम है, इस राज्य में 92% से अधिक मतदाताओं ने नरिवाचन आयोग के साथ अपना आधार वविरण साझा किया है।
- आधार लकिगि दर में लक्षद्वीप दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जहाँ क्रमशः 91% एवं 86% से अधिक मतदाताओं ने आधार संख्या को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा है।
- दक्षिणी राज्यों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में आधार पंजीकरण का अनुपात कम है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यह दर 71% है, तमलिनाडु तथा केरल में यह क्रमशः लगभग 63% और 61% है।
- गुजरात में मतदाताओं का आधार पंजीकरण सबसे कम है, केवल 31.5% मतदाताओं ने आधार को अपने मतदाता पंजीकरण से लकि किया है।
 - साथ ही दल्लि में 34% से भी कम मतदाताओं के आधार मतदाता पहचान पत्र से जुड़े (लकिड) हुए हैं।

सरकार द्वारा मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने पर ज़ोर देने का कारण:

- डेटाबेस को अद्यतित करना:
 - इस लकिगि परियोजना से चुनाव आयोग को काफी मदद मल्लिगी, जो आए दनिमतदाता आधार के अद्यतन और सटीक रकिॉर्ड को बनाए रखने के लिये नयिमति अभ्यास करता रहता है।
- प्रतलिपियिों (Duplicate) को हटाना:
 - मतदाताओं के दोहराव को समाप्त करना, उदाहरण के लिये [प्रवासी शरमकि](#), जनिका वभिनिन नरिवाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में एक से अधिक बार पंजीकरण अथवा कसिी वयक्तद्वारा एक ही नरिवाचन क्षेत्र में कई बार पंजीकरण कराया जाना, अतः इस प्रकार की समस्याओं से नपिटने के लिये प्रतलिपियिों को हटाने का कार्य किया जा सकता है।
- अखलि भारतीय मतदाता पहचान पत्र:
 - सरकार के अनुसार, आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने से यह सुनिश्चित करने में मदद मल्लिगी कि भारत के प्रत्येक नागरकि को केवल एक मतदाता पहचान पत्र जारी किया गया है।

आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने संबंधी मुद्दे:

- अस्पष्ट संवैधानकि स्थिति:
 - पुट्टासुवामी मामले (गोपनीयता का अधिकार) में सर्वोच्च न्यायालय ने जनि प्रश्नों की पड़ताल की उनमें से एक यह था कि क्यारबैंक खातों के साथ आधार को अनवार्य रूप से जोड़ना संवैधानकि है या नहीं।
- भनिन उद्देश्य:
 - मतदाताओं का नरिधारण करने के उद्देश्य से आधार को प्राथमकिता देना हैरान करने वाला है क्योंकि आधार केवल नवास का प्रमाण है, न कि नागरकिता का प्रमाण।

- इसलिये इसके द्वारा मतदाता पहचान को सत्यापित करने से केवल दोहराव से नपिटने में मदद मिलेगी, लेकिन यह मतदाता सूची से उन मतदाताओं को नहीं हटाएगा जो भारत के नागरिक नहीं हैं।

आगे की राह

- मतदाता पहचान पत्र को आधार से लकित करने के कार्य को आगे बढ़ाने के साथ सरकार [डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण \(DPDP\) अधियक, 2022](#) को लागू करने हेतु भी तत्पर है। DPDP व्यवस्था को सरकारी संस्थाओं पर भी लागू होना चाहिये जिसमें उन्हें वभिन्न सरकारी संस्थानों में अपने डेटा को साझा करने से पूरव कसी व्यक्ति की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

??????:

नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. आधार कार्ड का प्रयोग नागरकित्ता या अधविस के प्रमाण के रूप में कयिा जा सकता है।
2. एक बार जारी करने के पश्चात् इसे नरिगत करने वाला प्राधकिरण आधार संख्या को नषिक्रयि या लुप्त नहीं कर सकता है।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. नजित्ता के अधकिार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में मौलकि अधकिारों के वसितार का परीक्षण कीजयि। (2017)

[स्रोत: द हद्रि](#)